**20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में किसे क्या मिला? जानें- वित्त मंत्री की बड़ी बातें**

**बिहार में एक-एक थानेदार की खंगाली जा रही कुंडली, भ्रष्ट अफसरों पर लिया गया है कड़ा फैसला**

**लॉकडाउन में स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे आवारा पशु, सामाजिक संस्था ग्रीन एंड क्लीन के तत्वावधान में कई पार्षदों और आम लोगों ने नगर परिषद को मांगपत्र सौंपा**

**पीएम केयर्स फंड से कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी, 2000 करोड़ से वेंटीलेटर तो 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर किए जाएंगे खर्च**


युवराज न्यूज़ टुडे

NEWS TODAY Update www.newstodayupdate.in

RNI:- BIHHIN05409

www.newstodayupdate.in

आपकी आवाज़

राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

वर्ष : 06 अंक : 08+14 तिथि : 14 मई 2020 मूल्य : निःशुल्क प्रधान संपादक : डा. राजेश अस्थाना – 9471005272, 8210595830

email: newstodaymth@gmail.com website : newstodayupdate.in


बिग ब्रेकिंग

# न्यूज़ टुडे लॉक डाऊन स्पेशल रोजाना अंक

## 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में किसे क्या मिला? जानें- वित्त मंत्री की बड़ी बातें

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,

बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दे रही हैं. टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसदी की राहत मिली है.

बता दें कि सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स जुटाती है. टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है. इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल हैं .रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगा कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए. डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपये दी जाएगी.

नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है. इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा.एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा. वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा, इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा.

ईपीएफ पर बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी . 12 फीसदी की रकम EPFO में जमा करेगी. इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा. बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने ही कंट्रीब्यूट किया था.मतलब ये कि इस सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं. सरकार की इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है. यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.कर्मचारियों का 12 फीसदी की जगह 10 फीसदी ईपीएफ कटेगा. हालांकि पीएसयू में 12 फीसदी ही ईपीएफ कटेगा.एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदल दी गई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है. इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है. 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा.इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा.निर्मला सीतारमण ने बताया कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर संभव नहीं है.200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा. यह एमएसएमई के लिए बड़ा कदम है.

इसके अलावा एमएसएमई को ई–मार्केट से जोड़ा जाएगा. सरकार एमएसएमई के बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी.वित्त मंत्री के मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को जाएंगे. इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा. इसकी समयसीमा 4 साल की होगी. इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी. ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है.वित्त मंत्री के मुताबिक जो एमएसएमई तनाव में हैं उन्हें सबआर्डिनेट डेट के माध्यम से 20000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी. बता दें कि एसएमई में लघु और मझोले कारोबार आते हैं.

वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी.वित्त मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए.वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है.वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे.

## बिहार में एक-एक थानेदार की खंगाली जा रही कुंडली, भ्रष्ट अफसरों पर लिया गया है कड़ा फैसला

आशीष राज,
स्थानीय संपादक,

बिहार में दबंगई के लिए बदनाम थानेदारों की छवि बदलने की पहल की जा रही है। अच्छे आचार–व्यवहार वाले थानेदार सम्मा. नित होंगे और भ्रष्ट–बदनाम थानेदारों की काउंसिलिंग होगी। एक मौका दिया जाएगा। नहीं सुधरे तो हटा दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की मानें तो एक–एक थानेदार की कुंडली खंगाली जाएगी।

थानेदारों की छवि का कराया जाएगा मूल्यांकन

पुलिस मुख्यालय ने बिहार के 1100 थानेदारों की कुंडली खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास यह है कि एक–दो नहीं, बल्कि तीन माध्यम से थानेदारों की छवि का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके आधार पर प्रत्येक जिले से पांच उम्दा और पांच लचर काम करने वाले थानेदारों को चिह्नित किया जाएगा। पांच पैमाने पर मॉनीटरिंग रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें पुलिस महकमे के अलावा दो अन्य माध्यमों को जिम्मेदारी दी गई है। मूल्यांकन में मुख्य रूप से कोरोना संकट के दौरान पुलिस की सामाजिक सरोकार से संबंधित छवि पर विशेष फोकस रहेगा।

1500 से अधिक थाने और ओपी हैं बिहार में

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास कार्यक्रम के तहत पुलिस यह नवाचार कर रही है। बिहार में 1500 से अधिक थाने और ओपी हैं। इनमें थानों की संख्या करीब 1100 है। कोशिश है कि पुलिस के खिलाफ बढ़ती नकारात्मक धारणा में सुधार किया जाए। जनता के बीच पुलिस के मानवीय चेहरे को उभारा जाए। खासकर महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों में जागरूकता पैदा की जाए। इसके विशेषज्ञों को लगाया गया है।

डीजी टीम करेगी मूल्यांकन

जिलों से आई रिपोर्ट के मूल्यांकन की जिम्मेवारी पुलिस मुख्यालय स्तर पर डीजी टीम को दी जाएगी। उम्दा काम करने वाले थानेदारों को जहां प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, वहीं लचर थानेदारों को पुलिस मुख्यालय बुलाकर काउंसिलिंग का प्रावधान किया गया है।

पांच बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट

1. कर्तव्यनिष्ठा, 2. छवि, 3. सेवाभाव, 4. आम जनता खासकर कमजोर, शोषित दलित और अकलियतों के बीच संदेश, 5. जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार।

## लॉकडाउन में स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे आवारा पशु, सामाजिक संस्था ग्रीन एंड क्लीन के तत्वावधान में कई पार्षदों और आम लोगों ने नगर परिषद को मांगपत्र सौंपा

सम्राट, संवाददाता

वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से बचने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर परिषद से लेकर सामाजिक संस्थाएं तक जुटी हुई हैं। लॉकडाउन के साथ–साथ कई ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कसरत पर आवारा पशु पानी फेर दे रहे हैं। शहर का ज्ञान बाबू चौक हो या गांधी चौक, चांदमारी हो या बलुआ हर जगह आवारा पशु गंदगी फैला कर साफ–सफाई अभियान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरवासियों को डर है कि इनकी वजह से स्थिति भयावह न हो जाए। बुधवार को सामाजिक संस्था ग्रीन एंड क्लीन के तत्वावधान में कई पार्षदों और आम लोगों ने इस मसले को लेकर नगर परिषद को मा. गपत्र सौंप कर आवारा पशुओं से तुरंत निजात दिलाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी को देखते हुए शहर में साफ सफाई की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। नगर परिषद के कर्मचारी प्रतिदिन अपना वाहन निकालते हैं। वे शहर के प्रत्येक हिस्से में जाते हैं और गंदगी को उठाते हैं। वहीं ग्रीन एंड क्लीन जैसी सामाजिक संस्थाएं शहर में सेनेटाइजर का छिड़काव करने, मास्क उपलब्ध कराने, हैंड सेनेटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने में लगी हैं। इसके सदस्य स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। नगर परिषद और सामाजिक संस्थाओं का काम तब निरर्थक साबित हो जाता है, जब आवारा पशु स्वच्छता को गंदगी में तबदील कर देते हैं। इन दिनों सड़कों पर आवारा पशुओं की अचानक बाढ़ आ गई है।
मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर आवारा गायों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। लॉकडाउन में पशुपालकों को अपनी गायों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गायों को बाड़ में रखने के बजाय खुला छोड़ दिया है। ये गायें गंदगी और कूड़ा स्थलों पर भोजन तलाशती हैं। पेट भर भोजन नहीं मिलने पर पॉलीथिन व अन्य वस्तुएं खा ले रही हैं। इन्हीं गायों से सुबह– सुबह दूध दोहा जाता है। फिर इसी दूध को लोग पीते हैं। अब खुद अंदाजा लगाइए कि इस दूध को पीने वाला किन–किन बीमारियों की चपेट में आएगा। सुबह दूध दुहने के बाद गायों को खुला छोड़ देना सीधा–सीधा आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसी भी गायें हैं जो दूध नहीं देतीं और वे हमेशा सड़कों पर ही विचरती रहती हैं।
वहीं, सुअरों की वजह से भी शहर में गंदगी फैली रह रही है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जानपुल हो या स्टेशन रोड, मिस्कौट हो या चांदमारी के मोहल्ले, हर जगह आवारा सुअरों का बोलबाला है। गांधी चौक को तो मानों सुअरों ने अपना आराम स्थल बना लिया है। कूड़े के ढेर पर वे हमेशा लोटते रहते हैं। इन्हें देख कर ऐसा लगता है कि मानों वे सफाई कर्मचारियों चिढ़ा रहे हों कि तुम चाहे कुछ भी कर लो वे ऐसे ही गंदगी फैलाएंगे।
लॉकडाउन में कमोबेस यही हाल कुत्तों का भी है। कुत्तों को इनके मालिकों ने सड़कों पर छोड़ दिया है। भोजन की तलाश में वे इधर– उधर मंडराते रहते हैं। कई बार तो वे राहगीरों पर हमला कर देते हैं। चौक चौराहों पर गंदगी के ढेर पर ऐसे कई दृश्य देखे गए कि कभी कुत्ते, सुअर के मुंह से खाने के लिए गंदगी छीन रहे हैं तो कभी सुअर, गाय और कुत्तों के मुंह से। कुल मिला कर शहर के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। आवारा पशुओं ने गंदगी को हर जगह फैला दिया है। बदबू से बुरा हाल है।
डेढ़ माह से शहर को सेनेटाइज और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही सामाजिक संस्था ग्रीन एंड क्लीन के संस्थापक अध्यक्ष और नगर पार्षद अमरेंद्र सिंह कहते हैं कि हम लोग लगातार पशुपालकों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने पशुओं को तय स्थान पर ही रखें। उन्हें खुला न छोड़ें। लॉकडाउन में विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इसका असर नहीं हो रहा है। जो भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वो सब बेकार साबित हो रहा है। नगर परिषद को अब सख्ती बरतने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं किया गया तो अब जनता सड़कों पर उतर जाएगी.
नगर परिषद को मांग पत्र सौंपने वालों में रिटायर शिक्षक अमित सेन, हरीश कुमार, अजय वर्मा, सुधीर कुमार गुप्ता, संजय कुमार उर्फ टुन्ना, आलोक रंजन, वार्ड संख्या 5 के पार्षद पति हरीश कुमार, वार्ड 9 के पार्षद विजय जायसवाल, विवेक श्रीवास्तव, अर्जुन कुमार, विनय स्वर्णकार आदि प्रमुख थे।

## देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे किस्त को लेकर आज एलान, पैकेज के इस दूसरे चरण में किसान, मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को राहत

ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे किस्त को लेकर आज एलान कर रही हैं। उन्होंने कृषि कर्ज पर इंटरेस्ट सब्वेंशन और प्रॉम्पट रिपेमेंट इंसेंटिव का लाभ अब 31 मई, 2020 तक देने की बात कही। वित्त मंत्री ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी का एलान भी किया। उन्होंने कहा कि आज प्रवासी मजदूरों, किसानों, स्वरोजगारों की बात होगी, जो 9 घोषणाएं की जाएंगी उनमें से 3 प्रवासी मजदूरों के लिए होगी वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना देश के गरीब लोगों के लिए था।आइये जानते हैं, वित्त मंत्री की आज की बड़ी घोषणा...
क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विवरण देते हुए कहा कि तीन करोड़ सीमांत किसानों ने किफायती दरों पर चार लाख करोड़ रुपये का लोन प्राप्त किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च में रूरल इंफ्रा फंड के तहत राज्यों को 4200 करोड़ रुपए दिये गए।
मार्च, अप्रैल में 86600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि लोन मंजूर किए।
मार्च, 2020 में ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 4,209 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी गई।
एक मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के बीच कृषि के लिए 86,600 करोड़ रुपये का लोन दिया गया।
9 योजनाओं में से 2 योजना छोटे किसानों से संबंधित,3 अप्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी योजना
लोन मोरेटोरियम का तीन करोड़ किसानों ने फायदा उठाया।
किसान लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 31 मई तक बढ़ाई गई।
दो महीने में 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
कृषि ऋण पर इंटरेस्ट सब्वेंशन और प्रॉम्पट रिपेमेंट इंसेंटिव का लाभ अब 31 मई, 2020 तक मिलेगा
25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी
आज प्रवासी मजदूरों, किसानों, स्वरोजगारों की बात
9 में से 3 प्रवासी मजदूरों के लिए

## पीएम केयर्स फंड से कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी, 2000 करोड़ से वेंटीलेटर तो 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर किए जाएंगे खर्च

पीएम केयर्स फंड से कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि से 2000 करोड़ से वेंटीलेटर खरीदे जाएंगे जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मद में निर्धारित 3100 करोड़ में शेष 100 करोड़ की राशि कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर खर्च की जाएगी।

पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 करोड़

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर तेज हो रही राजनीति के बीच सरकार ने पीएम केयर्स फंड से उनके आवागमन, खानपान, चिकित्सा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्यों को दिया गया यह फंड जिलाधिकारी और निगम आयुक्त के अधीन रहेगा। राज्यों में सरकारी की तरफ से चलाए जा रहे कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में भारत में निर्मित 50 हजार वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वैक्सीन विकास के लिए जारी फंड का उपयोग प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की निगरानी में होगा।

## कोरोना वायरस की बचाव व चमकी बुखार की रोकथाम के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हैं आंगनबाड़ी सेविका

रिंकू गिरी,
संवाददाता

चकिया सीडीपीओ कार्यालय में बुधवार को प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच सैनिटाइजर का वितरण विधायक श्यामबाबू यादव ने किया। सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री के सौजन्य से यह सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था।
इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करते हुए विधायक श्री यादव ने कहा कि कोरोना वायरस की बचाव व चमकी बुखार की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी सेविका दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हैं एवं करोना को हराने में लगी हैं।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों ने पंचायतों में चौप. ालों को आयोजित कर जागरूकता अभियान में सहयोग का दायित्व निभा रही हैं। गरीब बस्तियों में जाकर चमकी बुखार के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं। क्वॉरेंटाइन सेंटर में जहां महिलाएं होती है वहां भी आंगनबाड़ी सेविका सहयोग कर रही हैं।
इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रोहित सिंह, सुधीर मिश्रा, विशाल कुमार, नीरज सिंह मनीष गुप्ता मौजूद थे।

## माँ नरदेवी प्रोडक्शन द्वारा पूरे शहर में तैनात पुलिसकर्मियों के पूरे बॉडी को किया जा रहा है सेनेटाइज

अफजल आलम
न्यूज टुडे,

आज जहां हर कोई हमारे करोना योद्धाओं को अपने अपने तरीके से मदद करने में लगे हैं वही कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी मे बेहतर कार्य करने वाले सभी सरकारी पदाधिकारियों व कर्मियों को माँ नरदेवी प्रोडक्शन द्वारा संस्थापक नीरज सिन्हा के नेतृत्व में पूरे शहर में तीन टुकड़ियों में बंटकर 4जहां भी चेक पोस्ट हैं वहाँ तैनात पुलिसकर्मी जो दिन भर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनके पूरे बॉडी को सेनेटाइज कर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है।

इस अनुकरणीय सत्य स्वरूप, पंकज, राजन, सन्नी, रुमित रौशन तथा राजीव अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। इस नेक कार्य में सहयोग करने के लिए जिला पुलिस ने टीम के सदस्यों का आभार प्रकट किया।


Yuvaraj Media & Entertainment
बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830